

प्रेषक,

विनीता कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष,

कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था समिति/

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून दिनांक 25 सितम्बर, 2008

विषय:-बैरागी कैम्प स्थित मायापुर स्केप चैनल के बायें किनारे पर आयरिश पुल से सतीघाट तक घाट के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-298/कु.मे.-2010/आगणन, दिनांक 11-6-2008 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई खण्ड, हरिद्वार द्वारा बैरागी कैम्प स्थित मायापुर स्केप चैनल के बायें किनारे पर आयरिश पुल से सतीघाट तक घाट के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु0 490.70 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु0 412.43 लाख (रु0 चार करोड़ बारह लाख तैतालिस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 200.00 लाख (रु0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए। उक्त के साथ एक तृतीय पक्ष से भी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 की व्यवस्थानुसार क्वालिटी कन्ट्रोल की व्यवस्था करके उक्त कार्य की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
2. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे। शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत

नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

3. प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 3-9-2008 को कुम्भ मेला, 2010 के कार्यों हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता परन्तु कम से कम तीन किस्तों में, पूर्व किस्त के 80 प्रतिशत उपयोग के बाद ही आगामी किस्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा।
5. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
7. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
9. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन कड़ाई से किया जाए।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।
11. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।
12. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।
13. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
14. सचिव/उपाध्यक्ष, कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था समिति/हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पद हेतु आहरण वितरण कोड आबंटित न होने के कारण उक्त धनराशि का आहरण जिलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
15. उक्त धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही उक्त कार्य हेतु आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के 'अनुदान संख्या-13' के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-आयोजनागत-800-अन्य-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-07-हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधा" के अन्तर्गत मानक मद "20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।"

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 726/XXVII(2)/2008 दिनांक 17 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-127(1)/IV(2)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध कि साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
10. अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई खण्ड, हरिद्वार।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
अपर सचिव।